

[1996] सुप. 2 एस.सी.आर

पी.एस. राज्या

बनाम

बिहार राज्य

9 मई 1996

[डॉ. ए.एस. आनंद और के. वेंकटस्वामी, न्यायमूर्ति गण]

*भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947:*

धारा 5(2) को धारा.5(1)(ड) के साथ पढ़ते हुए-आयकर अधिकारी- उसकी आय से अधिक संपत्ति पाए जाने का आरोप - केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही - विभागीय जांच समाप्त हुई केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अपराधी को दोषमुक्त करना, जिसे संघ लोक सेवा आयोग ने सहमति दी थी - केंद्रीय सतर्कता आयोग ने आयकर विभाग द्वारा किए गए संपत्ति के मूल्यांकन को कर्मचारी की आय से अधिक नहीं पाया - आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई उच्च न्यायालय-मामले के विशिष्ट तथ्यों के आधार पर, अपीलकर्ता के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है-विभागीय कार्यवाही और आपराधिक कार्यवाही में आरोप एक ही है-केंद्रीय जांच ब्यूरो का आचरण। मामले से निपटने में और जिस तरीके से उसने संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कराया, उसकी सराहना नहीं की जा सकती।

*दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:*

धारा 482-आपराधिक कार्यवाही-समान आरोपों पर विभागीय कार्यवाही में कर्मचारी को दोषमुक्त करने का प्रभाव-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक कार्यवाही-संपत्ति का मूल्यांकन अभियोजन का आधार-स्वयं समान आरोपों पर विभागीय कार्यवाही का समापन केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अपराधी को दोषमुक्त करना, जिसे संघ लोक सेवा आयोग ने सहमति दी थी - उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक कार्यवाही को रद्द

करने की याचिका खारिज कर दी गई, किसी आपराधिक मामले में अपराध स्थापित करने के लिए आवश्यक सबूत का मानक विभागीय कार्यवाही में अपराध स्थापित करने के लिए आवश्यक सबूत से कहीं अधिक है - जब समान आरोप विभागीय कार्यवाही में स्थापित नहीं किया जा सका, और रिपोर्ट में विसंगतियों को देखते हुए, वहाँ है कर्मचारी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही में आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं - ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है - पुनरावृत्ति।

हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य, [1992] अनुपूरक 1 एस.सी.आर. 335, पर भरोसा किया।

पी. सिराजुद्दीन बनाम मद्रास राज्य, [1970] 3 एस.सी.आर. 931, संदर्भित.

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 434/1996।

पटना उच्च न्यायालय के आपराधिक विविध अपील संख्या 5212/1992 में दिनांक 3.8.93 के निर्णय और आदेश से।

प्रशांत भूषण अपीलकर्ता की ओर से।

बी.बी. सिंह, पी. परमेश्वरन, और एस.एन.टेरडोल उत्तरदाताओं के लिए ।

न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया:

**न्यायमूर्ति, के. वेंकटस्वामी;** दोनो पक्षों के विद्वान वकील को सुना।

हमारे आदेश दिनांक 27.3.1996 द्वारा लागत के साथ अपील की अनुमति दी गई थी। कारणों को बाद में देने के लिए आरक्षित कर दिया गया था। अब कारण दिए गए हैं।

इस अपील में हमारे विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिवादी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 की धारा 5(2) को धारा 5(1)(ड) के साथ पढ़ते हुए तहत अपीलकर्ता के खिलाफ अभियोजन चलाना उचित है? कि एक समान आरोप पर अपीलकर्ता को केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट

और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सहमति के आलोक में विभागीय कार्यवाही से दोषमुक्त कर दिया गया था।

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

अपीलकर्ता ने वर्ष 1955 में एक कॉलेज में अपना करियर शुरू किया और वर्ष 1959 में टाटा लौह और इस्पात कंपनी में चले गए जब तक कि उन्हें 1961 में आयकर सेवा में निरीक्षक के रूप में चुना और नियुक्त नहीं किया गया। अपीलकर्ता की पत्नी भी बोकारो स्टील सिटी के सेंट्रल स्कूल में शिक्षिका थी। उन्हें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (संक्षेप में "सेल") द्वारा वर्ष 1980 में बोकारो में 20,000 रुपये की राशि में एक भूखंड लंबे पट्टे पर आवंटित किया गया था। सेल द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों के अनुसार, भूतल और पहली मंजिल पर निवास में दुकानों का निर्माण अपीलकर्ता ने अपनी कमाई के साथ-साथ अपनी पत्नी की कमाई से किया था। निर्माण सख्ती से पर्यवेक्षण के तहत था और सेल टाउनशिप प्राधिकरण द्वारा स्वतंत्र रूप से आपूर्ति किए गए ड्राइंग पर था। इसके बाद सेल टाउनशिप इंजीनियर ने इमारत की कीमत 4.75 लाख रुपये आंकी थी।

इस बीच अपीलकर्ता को पदोन्नति मिली और वह 1981 से 1985 तक ए-वार्ड धनबाद के आयकर अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान, उन्होंने कुछ व्यापारिक लोगों के खातों को जब्त कर लिया, जिन्होंने स्थानीय कांग्रेस पार्टी एमपी से शिकायत की थी, जिन्होंने अपीलकर्ता के बारे में वित्त मंत्री से शिकायत की और अपीलकर्ता को स्थानांतरित करने और सीबीआई जांच का आदेश देने का अनुरोध किया। तदनुसार, दिनांक 9-4-1986 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई और अपीलकर्ताओं के आवास और कार्यालय पर 11-4-86 को छापा मारा गया। हालांकि, उल्लेख करने लायक कुछ भी नहीं मिला। अंततः 31.7.89 को एक आरोप पत्र दायर किया गया जिसमें अपीलकर्ता की संपत्ति को नकदी, अचल संपत्ति (घर), और गहने निम्नलिखित अनुसार शामिल थे:

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| (i) बोकारो में भवन | रु. 7,69,300,00 |
| (ii) एन एस सी      | रु. 82,500.00   |

(iii) बैंक बैलेंस	रु. 1,584.91
(iv) घरेलू सामान	रु. 1,34,709.00
-----	
कुल	रु. 9,88,093.91
-----	

इसके मुकाबले, जांच अवधि (1973) से मार्च 1986) के लिए अनुमानित बचत 6,30,000 रुपये के रूप में निर्धारित की गई थी और उस आधार पर, यह आरोप लगाया गया कि संपत्ति 3,57,439 रुपये तक के अनुपात में नहीं थी।

उपरोक्त आरोप पर विशेष न्यायाधीश द्वारा संज्ञान लिए जाने से व्यथित अपीलकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत पटना उच्च न्यायालय में जाकर इसे चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने 3.8.90 के आदेश द्वारा याचिका को अनुमति दे दी और विशेष न्यायाधीश को मामले का संज्ञान लेने से पहले अपीलकर्ता के उच्च अधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच कराने या स्वयं करने का निर्देश दिया।

अपीलकर्ता का शिकायत यह है कि उच्च न्यायालय के रिमांड आदेश का सख्ती से पालन किए बिना, विशेष न्यायाधीश ने मामले का संज्ञान लिया और आगे बढ़ना चाहता था। उससे आहत होकर, अपीलकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत याचिका दायर की ताकि उपरोक्त उल्लेखित आरोप का संज्ञान रद्द कराया जा सके। इस बार उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि उसके सामने उठाए गए मुद्दों को अंतिम कार्यवाही में जाना होगा और उन्हें प्रारंभिक चरण में नहीं उठाया जा सकता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित अपीलकर्ता ने विशेष अनुमति द्वारा उपरोक्त अपील दायर की है।

अगर हम इस मामले के तथ्यों पर उस अभिव्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं, तो यह उल्लेख करना पूरी तरह से अनुचित नहीं हो सकता है कि अपीलकर्ता को कैसे सताया गया था।

प्रथम सूचना रिपोर्ट और उसके बाद की छापेमारी के आधार पर 24.11.86 को अपीलकर्ता को निलंबित कर दिया गया था। लगभग दो वर्षों तक कोई प्रगति नहीं हुई, जिससे अपीलकर्ता को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कलकत्ता ("कैट" के लिए संक्षिप्त नाम) में जाने के लिए बाध्य किया गया। 1.6.88 को अधिकरण ने सरकार को तीन महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया, अन्यथा निलंबन का आदेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। चूंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कैट द्वारा निर्देशित अनुसार जांच पूरी नहीं की, इसलिए निलंबन स्वतः निरस्त हो गया इसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 27.9.88 को तीन सी.पी.डब्ल्यू.डी. इंजीनियरों की एक टीम द्वारा अपीलकर्ता के घर का निरीक्षण कराया, जिस तारीख को अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्य बाहर थे और घर पर ताला बंद था। अपीलकर्ता को अपना पदोन्नति आदेश को हासिल करने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना जाना पड़ा और इस क्रम में अधिकरण ने अधिकारियों के खिलाफ कुछ कठोर आदेश पारित किए। अंत में, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 31.7.89 को एक चार्जशीट दाखिल की और इस चार्जशीट का मुख्य आधार बोकारो में अपीलकर्ता के घर का मूल्यांकन था, जिसे केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 7,69,300.00 रुपये तय किया था, जबकि आयकर विभाग द्वारा पहले किया गया मूल्यांकन 4.67 लाख रुपये था।"

हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि अपीलकर्ता के विद्वान वकील और प्रतिवादी के वरिष्ठ वकील दोनों द्वारा तर्कों को संबोधित करने का एकमात्र आधार बोकारो में अपीलकर्ता के घर के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा तय किए गए मूल्यांकन के आसपास केंद्रित था।

विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोप का संज्ञान लेने के तुरंत बाद, अपीलकर्ता को फिर से 31.5.90 को निलंबित कर दिया गया। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पटना उच्च न्यायालय ने 3.8.90 के आदेश द्वारा विशेष न्यायाधीश द्वारा लिया गया संज्ञान रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए वापस भेज दिया। अपीलकर्ता ने फिर से पदोन्नति और अन्य राहत के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना का रुख

किया, जिसने बदले में निलंबन आदेश को रद्द करने और 1987 से सभी वेतन वृद्धि जारी करने और सीलबंद कवर को खोलने का निर्देश दिया, जिसमें विभाग द्वारा अपीलकर्ता के पदोन्नति आदेश को रखा गया था। कैट के उस आदेश को विभाग द्वारा इस न्यायालय में चुनौती दी गई थी और इस न्यायालय ने 14-10-91 को विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही अपीलकर्ता को एक विभागीय आरोप पत्र दिया गया जिसमें समान आरोप थे। दो वर्षों से अधिक समय तक विभाग द्वारा कोई प्रगति नहीं की गई क्योंकि कोई जांच अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था। फिर, अपीलकर्ता को विभागीय चार्जशीट को रद्द करने के लिए कैट, पटना जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कैट, पटना द्वारा दिनांक 22-02-1993 को विभागीय जांच 15-05-1995 तक पूरी करने का निदेश दिया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग ने एक विस्तृत जांच के बाद अपीलकर्ता को सभी आरोपों से मुक्त करते हुए एक रिपोर्ट सौंपने के बाद विभागीय जांच की थी। विभाग ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट को संघ लोक सेवा आयोग की राय के लिए भेज दिया। एक लंबी रिपोर्ट द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग ने अपीलकर्ता को सभी आरोपों से मुक्त करने के निष्कर्ष के साथ सहमति व्यक्त की। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए, राष्ट्रपति ने अपीलकर्ता के पक्ष में अंतिम आदेश पारित किए। इसके बावजूद हमें बताया गया है कि अपीलकर्ता को पूर्ण सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिला है।

अब मामले के गुण-दोष पर लौटते अपीलकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की समान विभागीय आरोप से संबंधित स्पष्ट रिपोर्टों को देखते हुए, अभियोजन पक्ष के पास आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के विशेष न्यायाधीश को आरोप पत्र का संज्ञान लेने से पहले स्वयं या अपीलकर्ता के उच्च अधिकारियों के माध्यम से प्रारंभिक जांच करने के निर्देश के बावजूद, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने बिना किसी प्रारंभिक जांच के फिर से संज्ञान लिया है। विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोप पत्र का संज्ञान लेने का आदेश, जो उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, कायम नहीं रह सकता। इस बिंदु पर, उन्होंने पी सिराजुद्दीन बनाम केरल के मामले में इस न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया। मद्रास राज्य, [1970] 3 एस.सी.आर. श्री प्रशांत भूषण के अनुसार, विभागीय जांच के परिणाम को प्रारंभिक जांच के रूप में लिया जाना चाहिए और दोषमुक्ति आदेश को ध्यान में

रखते हुए, आपराधिक आरोप में आगे की कार्यवाही को हटा दिया जाना चाहिए। अपीलकर्ता के वकील ने आगे कहा कि जिन इंजीनियरों ने पहले आयकर विभाग को रिपोर्ट दी थी, वे ही संभवतः दबाव में केंद्रीय जांच ब्यूरो के कहने पर अलग-अलग मूल्यांकन दे चुके हैं और यहां भी कई स्थानों पर जरूरत से ज्यादा लेखन और बदलाव हुए हैं। विद्वान वकील के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस पहलू पर विस्तार से चर्चा की है और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि बाद की मूल्यांकन रिपोर्ट, जिन पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भरोसा किया था, संदिग्ध प्रकृति की हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने भी यही राय दी। वैसे भी चार्जशीट का आधार होने वाला मूल्य मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा बाद में दी गई रिपोर्ट में दिए गए मूल्य का नहीं है।

प्रतिवादी के लिए पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मलहोत्रा ने तर्क दिया कि दोनों ही विद्वान विशेष न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को अंतिम सुनवाई में अपना मामला स्थापित करने से नहीं रोका है और अब उठाए गए बिंदु बहुत अच्छी तरह से दिए गए सबूतों से स्थापित किए जा सकते हैं। उचित समय और स्वयं आरोप को रद्द करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है। विद्वान वकील के अनुसार, विभागीय जांच के तहत दिए गए निष्कर्षों के बावजूद, केंद्रीय जांच ब्यूरो को उपलब्ध सामग्री के आधार पर आगे बढ़ने का अधिकार है और केवल यह आरोप कि भवन के मूल्य के संबंध में रिपोर्ट संदिग्ध प्रकृति की थी, सबूत का स्थान नहीं लेगी और इसे अंतिम सुनवाई में संबंधित मूल्यांकनकर्ताओं के साक्ष्य लेने के बाद जाना और स्थापित किया जाना है। इसलिए, उन्होंने विद्वान विशेष न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश का समर्थन किया।"

शुरु में, हम बता सकते हैं कि प्रतिवादी के विद्वान वकील इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सके ने इस बात को स्वीकार किया कि आपराधिक मामले में दोष साबित करने के लिए आवश्यक सबूत का मानक विभागीय कार्यवाही में दोष साबित करने के लिए आवश्यक सबूत के मानक से कहीं अधिक है।"उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वर्तमान मामले में, विभागीय कार्यवाही और आपराधिक कार्यवाही में आरोप एक ही है। उन्होंने विभागीय कार्यवाही में दिए गए निष्कर्षों और उसके अंतिम परिणाम पर विवाद नहीं किया। इन आधारों

पर यदि हम आगे बढ़ें तो अपीलकर्ता के मामले को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है। अगर जो आरोप समान है उसे स्थापित नहीं किया जा सका विभागीय कार्यवाही और मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में स्वीकृत विसंगतियों को देखते हुए, किसी को आश्चर्य होता है कि आपराधिक कार्यवाही में अपीलकर्ता के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए और क्या है। इस संदर्भ में, हम इस पहलू पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट से कुछ प्रासंगिक अंश उपयोगी रूप से निकाल सकते हैं।

"अदालत ने कहा, 'न तो अभियोजन पक्ष और न ही बचाव पक्ष ने मूल्यांकन की पुष्टि के लिए विभिन्न रिपोर्टों के लेखक को पेश किया है। दस्तावेजों की सूची में जिन दस्तावेजों का हवाला दिया गया है, वे दो इंजीनियरों श्री एस.एन. झा और डी.एन. मुखर्जी जबकि रिकॉर्ड में लाए गए दस्तावेज (दस्तावेज ध-20) पर तीन इंजीनियरों ने हस्ताक्षर किए हैं। आरोप पत्र और रिपोर्ट में संपत्ति के अनुमानित मूल्य में भी अंतर है। दस्तावेज ध-20 में तीन इंजीनियरों ने हस्ताक्षर किए हैं और संपत्ति का मूल्य पहली मंजिल के लिए 4,85,000 रुपये और दूसरी मंजिल के लिए 2,55,600 रुपये निर्धारित किया गया है। इसका कुल योग 7,40,900 रुपये आता है जो कि आरोप पत्र में बताए गए 7,69,800 रुपये के आंकड़े से पूरी तरह अलग है। मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने वाले किसी भी इंजीनियर ने हालांकि अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में उद्धृत नहीं हुए और जांच के दौरान उपस्थित नहीं हुए। यह बचाव पक्ष के तर्क का समर्थन करता है कि इस दस्तावेज की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह है। यह एक तथ्य है कि आयकर अधिकारियों ने इस संपत्ति का मूल्यांकन श्री. एस.एन. झा और वासुदेव से करवाया था और इस रिपोर्ट के अनुसार पृष्ठ 50 से 63 तक उन्होंने संपत्ति का अनुमान 4,57,600 रुपये लगाया था, जिसमें जमीन की लागत 1,82,000 रुपये भी शामिल थी। भूतल और मुख्य मंजिल के लिए प्लस 2,55,600 रुपये पहली मंजिल के लिए और 20,000 रुपये जमीन की लागत के लिए। इस प्रकार आयकर उद्देश्यों के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने वाले दोनों इंजीनियरों ने भी केंद्रीय जांच ब्यूरो के लिए रिपोर्ट तैयार की और बाद की रिपोर्ट में कोई संकेत नहीं है कि संपत्ति के मूल्य में अंतर क्यों है। इन दो रिपोर्टों के अवलोकन से पता चलता है कि काम के विनिर्देश में अंतर है। आयकर उद्देश्यों के लिए भूतल मंजिल के लिए श्री एस.एन. झा द्वारा तैयार मूल्यांकन रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संरचना में "आरसीसी पिलर, सीमेंट मोर्टार में ईट का काम, आरसीसी



लिटेल, 60 सेमी दीवारें, 9 इंच फर्श की ऊंचाई, 17.6, 8.00, 8.00 इंच" थे, लेकिन केंद्रीय जांच ब्यूरो के लिए रिपोर्ट में, जो उनके द्वारा भी तैयार की गई थी, विवरण "आरसीसी फ्रेम युक्त संरचना भूतल मंजिल में तीन तरफ खुली छत" है। इसी तरह, पहली मंजिल के लिए रिपोर्ट में लिखा है "आंशिक रूप से निर्मित संरचना और आंशिक रूप से लोडिंग दीवारें, फर्श की ऊंचाई 3.20 मिमी।" इसके अलावा, श्री एस.एन. झा ने पृष्ठ 54 पर दस्तावेज घ-1 में भूतल मंजिल के लिए 290 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर अपनाई थी और अतिरिक्त ऊंचाई के लिए जोड़ते हुए उन्होंने ग्राउंड फ्लोर सहित मेजेनाइन फर्श का अनुमान 2,02,600 रुपये लगाया था। लेकिन दस्तावेज ध-20 के लिए रिपोर्ट में दर बढ़ाकर 365 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दी गई है। इसमें 75 रुपये प्रति मीटर की दर में वृद्धि का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यह भी देखा गया है कि लागत को अद्यतन करने के लिए सूचकांक के 5-% को श्री एस.एन. झा द्वारा दस्तावेज घ-1 के पृष्ठ 55 के अनुसार 290 रुपये की दर में जोड़ा गया था, लेकिन इसे बढ़ाकर 97% कर दिया गया है। दस्तावेज ध-20 में लागत सूचकांक में स्पष्टीकरण या कारण बताए बिना। यह आश्चर्य की बात है कि इंजीनियरों के एक ही सेट ने एक ही संपत्ति के मूल्यांकन के लिए अलग-अलग समय पर अलग-अलग मानक अपनाए हैं। इसी प्रकार, पहली मंजिल के लिए इसे आंशिक रूप से फ्रेम की गई संरचना और आंशिक रूप से लोड के रूप में लिखा गया है, फर्श की ऊंचाई 3.20 मिमी है। इसके अलावा, श्री एसएन झा ने दस्तावेज घ -1 के पृष्ठ 54 पर भूतल के लिए 290 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर अपनाई थी और अतिरिक्त ऊंचाई के लिए उन्होंने मेजेनाइन मंजिल सहित भूतल का अनुमान 2,02,600 रुपये लगाया था। लेकिन दस्तावेज ध 20 की रिपोर्ट के लिए दर को बढ़ाकर 365 प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। जाहिर है, दोनों में से कोई एक रिपोर्ट झूठी है और अभियोजन पक्ष के लिए इसे उचित रूप से स्पष्ट करना था। इसकी अनुपस्थिति में एकमात्र निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि दस्तावेज ध-20 पर रिपोर्ट प्रामाणिक नहीं है। चूंकि इंजीनियरों के एक ही सेट ने पहले मूल्यांकन किया है और यदि बाद में उन्होंने महसूस किया कि पहले की रिपोर्ट में कोई त्रुटि थी, तो उन्हें विस्तृत कारणों को या तो रिपोर्ट में ही या जांच के दौरान स्पष्ट करना चाहिए था। इसलिए, दस्तावेज ध-20 विश्वसनीय नहीं है।"

20. इसके अलावा दस्तावेज ध-20 के पूर्व का अवलोकन से पता चलता है कि श्री. वासुदेव, कार्यकारी अभियंता ने एक नोट इस प्रकार दर्ज किया है:

"इसलिए श्री एस.एन. झा का मूल्यांकन कभी नहीं किया गया अतिक्रमण किसी अन्य अनुमान से जैसा कि रिकॉर्ड से पुष्टि होती है, उनके अनुमानित आंकड़े केवल आय करकार्यालय बोकारो द्वारा दर्ज किए गए थे",

इस प्रकार, श्री वासुदेव के अनुसार जो दस्तावेज ध-20 को तैयार करने वाले तीन सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियरों में सबसे वरिष्ठ थे। भूतल का मूल्यांकन 1,82,600 रुपये प्लस जमीन की लागत के लिए 20,000 रुपये पर बनी हुई है। दस्तावेज ध-20 के अनुसार पहली मंजिल का अनुमान 2,55,600 रुपये लगाया गया था और कुल मिलाकर यह सब 4,57,600 रुपये आता है जो आयकर प्राधिकरण को वास्तविकताओं की घोषणा और बोकारो स्टील टाउनशिप इंजीनियर और सरकार द्वारा अनुमानित लागत के बहुत करीब है। स्वीकृत मूल्यांकनकर्ता।

21. "उपरोक्त चर्चाओं से यह स्पष्ट है कि यद्यपि अनुबंध III में उद्धृत दस्तावेज दो इंजीनियरों की एक संयुक्त रिपोर्ट है, जिसे रिकॉर्ड पर लाया गया है वह तीन इंजीनियरों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज है, इंजीनियरों के एक ही समूह ने आयकर उद्देश्यों के लिए संपत्ति का मूल्यांकन किया है और पूर्व में लागत की गणना के लिए अनुकूलित विशिष्टताओं और दरों में बहुत बड़ा अंतर है। दस्तावेज ध-20 को बिना किसी स्पष्टीकरण के बढ़ा दिया गया है और इनमें से कोई भी इंजीनियर पूछताछ के दौरान स्थिति स्पष्ट करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए पूर्व की प्रामाणिकता. दस्तावेज ध-20 संदिग्ध है जैसा कि बचाव पक्ष ने दावा किया है।"

22. "यह उल्लेख करना आवश्यक है कि दस्तावेज ध-20 की रिपोर्ट में भूतल का मूल्यांकन रु. 4,85,300 और एक नोट भी दर्ज किया गया है कि स्वयं-पर्यवेक्षण और सामग्री की खरीद के लिए 10% की अनुमति दी जानी चाहिए इस आधार पर भूतल का शुद्ध मूल्य 4,36,810 रुपये (4,85,344 रुपये - 48,534 रुपये) आता है। पहली मंजिल का मूल्यांकन स्वयं-पर्यवेक्षण के लिए भत्ता देने के बाद 2,55,600 रुपये किया गया है और दोनों मर्दों का कुल 6,62,410 रुपये होगा। सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियरों की रिपोर्ट के अनुसार संपत्ति का मूल्य रु. 7,69,800 दस्तावेज ध-20 अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करता है। चूंकि संपत्ति का मूल्यांकन आयकर प्राधिकरण द्वारा रुपये के लिए किया गया है। चूंकि आयकर प्राधिकरण

द्वारा संपत्ति का मूल्यांकन 4.67 लाख रुपये किया गया था और यहां तक कि बोकारो स्टील टाउनशिप इंजीनियर और सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता द्वारा दिए गए मूल्यांकन भी इस आंकड़े के बहुत करीब हैं, इस संपत्ति का उचित मूल्य केवल 4.75 लाख ही लिया जा सकता है, जिसका मूल्यांकन बोकारो टाउनशिप इंजीनियर द्वारा विस्तृत अनुमान के आधार पर किया गया था।"

अपीलकर्ता को विभागीय कार्यवाही में तय किए गए आरोप से मुक्त करने के आदेश से एक अंश निकालना अनुचित नहीं होगा। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

"योग ने मामले के तथ्यों और रिकॉर्डों का सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद सलाह दी है कि आवेदक श्री पी.एस. राजा की बचत उनके द्वारा अर्जित संपत्तियों से अधिक थी और इसलिए, आय के अनुपात में संपत्तियों के अधिग्रहण के आरोप का आधार नहीं बनता है। आयोग द्वारा दी गई सलाह की एक प्रति संलग्न है। आयोग ने यह भी सलाह दी है कि न्याय की रक्षा के लिए आरोपित अधिकारी श्री पी.एस. राजा को बरी करना उचित होगा।

राष्ट्रपति ने मामले के तथ्यों और रिकॉर्ड और संघ लोक सेवा आयोग की सलाह पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। राष्ट्रपति इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की सलाह मान ली जाए। इसलिए, इसलिए, यह माना जाता है कि श्री राजा के खिलाफ आरोपित लेखों को साबित नहीं किया गया है। इसलिए, राष्ट्रपति श्री राज्य, सहायक कर निरीक्षक(सेवानिवृत्त) को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से मुक्त करते हुए और उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को समाप्त करने के लिए प्रसन्न हैं।"

हमारा मानना है कि उपरोक्त उद्धरण इस मुद्दे के बारे में सही तस्वीर देते हैं।

पुनरावृत्ति के जोखिम पर, हम कह सकते हैं कि आरोप साबित नहीं हुआ था और उस आधार पर अपीलकर्ता को विभागीय जांच से मुक्त कर दिया गया था, इस संबंध में, हम हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य, [1992] अनुपूरक 1 एस.सी.सी. 335 का इस न्यायालय के एक निर्णय का भी हवाला दे सकते हैं। इस न्यायालय ने लगभग सभी पूर्व निर्णयों पर विचार करने के बाद संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति या आपराधिक संहिता की धारा 482के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने के

लिए दिशानिर्देश दिए हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत को रद्द करने के लिए। इस न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किया;"

"अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग या धारा के तहत अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में संहिता के 482 जिसे हमने ऊपर निकाला और पुनः प्रस्तुत किया है, हम उदाहरण के तौर पर मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां देते हैं जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि यह संभव नहीं हो सकता है कि किसी भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से नियंत्रित और अनम्य दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित किए जाएं और ऐसे मामलों की विस्तृत सूची दी जाए जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए"

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप और प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ आने वाली अन्य सामग्री (यदि कोई हो) धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को न्यायसंगत नहीं बनाती है, सिवाय इसके कि धारा 155(2) के दायरे में किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत।

(3) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में निर्विवाद आरोप लगाए गए हैं और इसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

(4) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि केवल गैर-संज्ञेय अपराध हैं, वहां मजिस्ट्रेट द्वारा किसी जांच की अनुमति नहीं है, जैसा कि संहिता की धारा 155(2) के तहत माना गया है।

(5) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत एक अपराधी) के किसी भी प्रावधान में एक स्पष्ट कानूनी बाधा शामिल है कार्यवाही स्थापित किया गया है) संस्था को और कार्यवाही जारी रखने और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावना से भाग लिया जाता है और/या जहां कार्यवाही में भाग लिया जाता है अभियुक्त से प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य से तथा निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने की दृष्टि से दुर्भावनापूर्ण ढंग से स्थापित किया गया।

हम इस आशय की चेतावनी भी देते हैं कि किसी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग बहुत संयमित और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभतम मामलों में, कि प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा की जांच शुरू करना अदालत के लिए उचित नहीं होगा और असाधारण या अंतर्निहित शक्तियां अदालत को उसके अनुसार कार्य करने के लिए एक मनमाना क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती हैं। यह सनक है।"

वर्तमान मामले को बिना किसी कठिनाई के उपरोक्त से अधिक एक शीर्ष के अंतर्गत लाया जा सकता है।

उपरोक्त चर्चा इस मामले के तथ्यों पर इस अपील की अनुमति देने के लिए पर्याप्त है,

यद्यपि केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट सहित इन सभी तथ्यों को उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था, दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि उठाए गए मुद्दों को अंतिम कार्यवाही में जाना होगा और केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट, विभागीय कार्यवाही में उसी आरोप से अपीलकर्ता को बरी कर देगी और अपीलकर्ता के खिलाफ

आपराधिक मामला समाप्त नहीं होगा। हम पहले ही यह मान चुके हैं कि दिए गए कारणों से, इस मामले के विशिष्ट तथ्यों पर, अपीलकर्ता के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। इसलिए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। अपील की अनुमति देने के हमारे दिनांक 27.3.1996 के आदेश के यही कारण है और विवादित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना और परिणामी राहत देना।

इस मामले को समाप्त करने से पहले, हम इस तरह से केंद्रीय जांच ब्यूरो के आचरण के बारे में अपनी पीड़ा व्यक्त किए बिना नहीं रह सकते हैं। रिकॉर्ड से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष को वापस लेने के निर्देश प्राप्त करने के लिए कई स्थगन लिए गए थे। कई स्थगन लेने के बाद, अंततः विभाग ने मामले को अदालत के फैसले पर छोड़ने का फैसला किया।

इस संबंध में, अपीलकर्ता की ओर से दायर प्रत्युत्तर हलफनामे से एक अंश निर्धारित करना उपयोगी होगा जो इस प्रकार है:

"हालांकि, ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता/स्टंप के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने में क्षेत्रीय केंद्रीय जांच ब्यूरो की अनिच्छा इस तथ्य से बाधित है कि उन्होंने याचिकाकर्ता पर आरोप लगाने के लिए एकमात्र आधार के रूप में मकान मूल्यांकन रिपोर्ट का इस्तेमाल किया था। तथ्य यह है कि यह रिपोर्ट जाली है विशेष अनुमति याचिका में निर्धारित तथ्यों और परिस्थितियों से पूरी तरह से स्पष्ट है। इस रिपोर्ट के द्वारा याचिकाकर्ता के घर का मूल्य उसी इंजीनियर द्वारा मूल मूल्यांकन से लगभग 3 लाख रुपये और उससे अधिक आंकने की मांग की गई थी, जिसे आयकर विभाग ने स्वीकार कर लिया था। इस आधार पर, याचिकाकर्ता की संपत्ति आय के रूप में 3 रु लाख और उससे अधिक दिखाई गई थी।

याचिकाकर्ता ने वास्तव में धारा 340 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शिकायत दर्ज की है। संबंधित अधिकारी के खिलाफ याचिकाकर्ता पर आरोप लगाने में जाली दस्तावेज़ का उपयोग करने के लिए संज्ञान लेने के लिए। याचिकाकर्ता की यह शिकायत केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश (पटना) के समक्ष लंबित है। यह शायद जालसाजी दस्तावेज़ पर दोषी

पाए जाने के डर से है कि क्षेत्रीय केंद्रीय जांच ब्यूरो अधिकारी याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप वापस लेने के लिए अनिच्छुक हैं। यही कारण है कि इस न्यायालय से 6 अवसरों पर छोटी सी स्थगन लेने के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही वापस लेने में उन्हें सक्षम करने के लिए, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अपना रुख बदल दिया है और यहां तक कि उनके वरिष्ठ वकील ने भी अपनी जगह ले ली है।

ऊपर दिए गए उद्धरणों को हम इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अनदेखा नहीं कर सकते। इसे हल्के में लेते हुए, हम यह देखते हैं कि जिस तरह से केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले में आचरण किया है, हम उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। हमें यकीन है कि विभाग भविष्य में इस तरह की टिप्पणियों के लिए जगह छोड़ दी है।

आर.पी.

अपील की अनुमति दी गई।